भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2890

20 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

इस्पात के उपयोग में वृद्धि

2890. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में इस्पात के उपयोग को बढाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दस वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति इस्पात के खपत में वृद्धि आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) और (ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका नीतिगत दिशानिर्देशों को तैयार करने और देश में इस्पात उत्पादन, खपत को बढ़ाने तथा इस्पात क्षेत्र की दक्षता में सुधार करने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु संस्थागत प्रणाली/तंत्र की स्थापना करने की है। इस दिशा में, सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 जारी की है जिसमें वर्ष 2030-31 तक मांग एवं आपूर्ति दोनों पक्षों के लिए भारतीय इस्पात उद्योग के दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत रूपरेखा का निर्धारण किया गया है। सरकार द्वारा गति-शक्ति मास्टर प्लान के लिए पर्याप्त पूंजीगत निवेश के माध्यम से अवसंरचनात्मक विकास पर बल, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 'मेक-इन-इंडिया' पहल तथा सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं के द्वारा देश में इस्पात की मांग एवं खपत को बढ़ावा मिलेगा।

इस्पात मंत्रालय ने आवासन एवं निर्माण क्षेत्र में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए घरों के निर्माण एवं लौंग स्पैन वाले सड़क के पुलों हेतु इस्पात प्रधान डिजाइनों के विकास के लिए उद्योग तथा तकनीकी संस्थानों (आईआईटी/एनआईटी) के विशेषज्ञों की समिति का गठन किया है। स्वदेशी खपत के लिए विशेष इस्पात की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने देश के भीतर विशेष इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भी अधिसूचित किया है।

(ग) और (घ): कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020-21 को छोड़कर पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत में निरंतर वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	कुल तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत (कि.ग्रा में)
2013-14	59.2
2014-15	60.8
2015-16	63.5
2016-17	64.7
2017-18	69.0
2018-19	74.4
2019-20	74.7
2020-21	70.0
2021-22	77.2
2022-23	86.7
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)	

*****